

कार्यालय ज्ञापन

विषय: एपीडा पंजीकृत मांस निर्यातकों के लिए संशोधित दिशानिर्देश- बैंक गारंटी, टाई-अप व्यवस्था और उत्पादन क्षमता अनुपालन

अध्यक्ष, एपीडा की अध्यक्षता में 3 जनवरी 2025 को एपीडा कॉन्फ्रेंस हॉल में प्रमुख मांस निर्यातकों के साथ हुई बैठक के दौरान हुई चर्चा के अनुसरण में व्यापार के हित में निम्नलिखित निर्णय लिए गए हैं:

1. बैंक गारंटी (बीजी) आवश्यकता:

क. व्यापारी निर्यातकों के लिए बैंक गारंटी (बीजी) को 5 लाख रु. से संशोधित कर 25 लाख रु. कर दिया गया है।

ख. पंजीकरण के लिए आवेदन करने वाले नए व्यापारी निर्यातकों के लिए , संशोधित बीजी आवश्यकता 1 फरवरी 2025 से प्रभावी होगी।

ग. मौजूदा व्यापारी निर्यातकों को 1 अप्रैल 2025 तक पुनर्विधित बीजी और संशोधित समझौते प्रस्तुत करने होंगे।

2. टाई-अप व्यवस्था:

क. व्यापारी निर्यातकों और एकीकृत मांस इकाइयों/मांस प्रसंस्करण इकाइयों के बीच टाई-अप समझौतों की वैधता 11 महीने ही होगी।

ख. 1:2 अनुपात बनाया रखा जाएगा , अर्थात्, अधिकतम दो (2) व्यापारी निर्यातक निर्यात प्रयोजनों के लिए एक एकल मांस इकाई के साथ समझौता कर सकते हैं और इसके विपरीत भी।

ग. टाई-अप व्यवस्था सामान्यतः एक ही राज्य/संघ राज्य क्षेत्र के भीतर होगी , सिवाय उन मामलों को छोड़कर जैसा कि नीचे 'ग' में उल्लिखित है।

घ. व्यापारी निर्यातकों और एकीकृत मांस इकाइयों/मांस प्रसंस्करण इकाइयों सहित सभी हितधारकों को इस ओएम के जारी होने के 4 सप्ताह के भीतर एपीडा के साथ टाई-अप का विवरण और सहायक दस्तावेज प्रस्तुत करना होगा।

टाई-अप अनुपात में छूट:

क. यदि कोई व्यापारी निर्यातक एपीडा के साथ पंजीकृत अपनी स्वयं की समूह कंपनियों से मांस उत्पाद प्राप्त करता है।

ख. यदि व्यापारी निर्यातक ने एपीडा-पंजीकृत मांस प्रतिष्ठानों को दीर्घकालिक पट्टे पर लिया है और संपूर्ण उत्पादन विशेष रूप से इन इकाइयों से प्राप्त की गई हो।

ग. यदि उपरोक्त 'ख' में निर्धारित सभी उपलब्ध स्लॉट समाप्त होने के कारण राज्य में मौजूदा एकीकृत मांस इकाइयों/मांस प्रसंस्करण इकाइयों के साथ टाई-अप की कोई संभावना नहीं है , तो ऐसे मामलों में , संबंधित व्यापारी निर्यातक को अपने राज्य के बाहर एपीडा-पंजीकृत इकाई के साथ टाई-अप के लिए एपीडा की पूर्व अनुमति लेनी होगी।

3. उत्पादन क्षमता अनुपालन:

क. निर्यातकों को केवल निर्यात उद्देश्यों के लिए अनुमोदित उत्पादन क्षमताओं का सख्ती से पालन करना होगा।

ख. घरेलू खपत के लिए पशुबध मांस (यदि किया जा रहा है) को अनुमोदित क्षमता से घटाया जाएगा, जब तक कि प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा अलग से प्रमाणित न किया जाए। इसके लिए उचित रिकॉर्ड/दस्तावेज बनाए रखा जाएगा।

ग. अपनी अनुमोदित क्षमता से अधिक उत्पादन करने वाली किसी भी इकाई को विनियामक कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा।

सभी हितधारकों को इन निर्देशों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करना होगा। इन निर्देशों के किसी भी उल्लंघन से एपीडा अधिनियम, 1985 के तहत निर्धारित प्रावधानों के अनुसार निपटान किया जाएगा।

(डॉ. सुधांशु)
सचिव